

सम्पादकीय जनसंख्या का गणित

देश में विभिन्न दलों के राजनेता और धार्मिक नेता अपने तात्कालिक हितों की पूर्ण हेतु अपने लक्षित समूहों की आबादी बढ़ाने की जरूरत बताते रहे हैं। आबादी के बोझ से चरमराती नागरिक सेवाओं और सीमित संसाधनों के बीच आबादी बढ़ाने का आह्वान करना तार्किक दृष्टि से गले नहीं उतरता। लेकिन इसके बावजूद धार्मिक व सांप्रदायिक समूह के अगुआ आबादी बढ़ाने का आह्वान करते नजर आते हैं। इस विवादास्पद मुद्दे की हालिया चर्चा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भगवत की टिप्पणी के कारण पिछ सुर्खियों में है। उनका कहना है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। उन्होंने एक तस्वीर उकरते हुए कहा है कि जिस समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाएगी, कालांतर उस समाज को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनकी दलील है कि बहुसंख्यक समाज को हम दो, हमारे तीन के समाधान पर अमल करना चाहिए। यानी प्रत्येक जोड़े को कम से कम तीन बच्चे पैदा करने चाहिए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने एक समुदाय विशेष को इंगित करते हुए चिंता जातायी थी कि अधिक आबादी वाला समुदाय जनसंख्या संतुलन के लिये चुनौती पेश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस विवादास्पद भाषण के कुछ साहार के बाद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के निष्कर्ष में इस बात को लेकर चिंता जातायी गई थी कि 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक समाज की आबादी में 7.82 पीसदी की कमी आई है। वहीं देश के मुख्य अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में 43 पीसदी की वृद्धि हुई है। दरअसल, इन्हीं आंकड़ों के जरिये भविष्य में बहुसंख्यक समाज के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के रूप में पेश किया जाता है। दरअसल, राजनीतिक नेतृत्व व धार्मिक संगठनों के नेताओं द्वारा अपनी सुविधा की जनसंख्या नीति को लेकर जो दलीलें दी जा रही हैं, वे एक अर्थशास्त्री द्वारा लक्षित जनसंख्या की संकल्पना दृष्टि के महेनजर विरोधाभासी कही जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने में छोटे परिवार मददगार साबित हो सकते हैं। निश्चित रूप से जनसंख्या से जुड़ी विरोधाभासी दलीलों की तार्किकता तलाश पाना एक कठिन कार्य रहा है। लेकिन एक हकीकित यह भी है कि देश में परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक के प्रयोग में वृद्धि के कारण प्रजनन दर में काफ़ी गिरावट आई है। वहीं ऐसे ही तात्कालिक कारणों तथा राजनीतिक लक्ष्यों ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी सरकार को दो संतानों की नीति को खत्म करने के लिये प्रेरित किया है। ऐसी ही जनसंख्या नीति में बदलाव के लिये तमिलनाडु सरकार की तरफ से विरोधाभासी बयान विगत में सोशल मीडिया पर खबर चर्चा का विषय बने हैं। ऐसे हालात में विभिन्न राज्यों में सरकारों को चाहिए कि वे जनसंख्या नीति पर बयानबाजी करने से पहले उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करें। वे विचार करें कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन की चुनौती के बीच क्या वे अतिरिक्त जनसंख्या के बोझ को संभाल पाने में सक्षम हो सकते हैं? निस्संदेह, राजनीतिक और धार्मिक लक्ष्यों के लिये संख्या का खेल खेलने वाले नेताओं को सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना भले ही सफलता का शार्टकट लगता हो, लेकिन उन्हें भारत की दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिये ऐसे प्रयासों के निहिताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जाहिर बात है कि देश की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या का घनत्व पहले ही काफ़ी असंतुलित है। यदि पिछी भी जनसंख्या वृद्धि की होड़ संकीर्ण स्वार्थों के लिये की जाती है तो उसके दूरगामी घातक प्रभाव सामने आ सकते हैं। हमारी प्राथमिकता हर हथ को काम देने तथा

अडानी को जांच

के रवींद्रन

जनसंख्या पर भाजपायी विमर्श को बढ़ाते भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुजारिश की है और उसे जनसंख्या विज्ञान के 2.1 के फर्मूले से जोड़कर चाहे सियासी अर्थों को छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस बयान के पीछे उनके संगठन के बे ही पुराने गहन राजनीतिक मकसद मौजूद हैं जिसके लिये वह जानी जाती है— ध्वनीकरण। उनका बयान ऊपरी खुले तौर पर चाहे संघ की राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब तक की सोच के विपरीत दिखाई देता हो, जो देश के समाने अक्सर बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जाती आई है, परन्तु भागवत के बयान को भाजपा के लिये एक दिशानिर्देश की तरह भी देखा जा रहा है। बहुत सम्भव है कि केन्द्र सरकार भागवत के बयान के अनुकूल कोई ऐसी जनसंख्या नीति लेकर आये जिससे हिन्दुओं की आबादी को बढ़ाया जा सके। संघ और भाजपा जनसंख्या सम्बन्धी वास्तविक तथ्यों व आंकड़ों को दरकिनार कर यह प्रचारित करती आई है कि देश में हिन्दुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिमों की बढ़ रही है। देश में इस्लामोफोबिया बढ़ाने के लिये जनसंख्या को गलत तरीके से पेश करना संघ-भाजपा की पुरानी नीति है। अनेक महत्वपूर्ण मौकों पर भागवत हों या इन दो संगठनों से जुड़े लोग, इसका डर दिखाते रहे हैं। नागपुर में एक संगठन के सम्मेलन में दिये भाषण में भागवत ने कहा कि-2.1 की कम प्रजनन दर वाला समाज अपने आप नष्ट हो जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे कम जनसंख्या वाला समाज तब भी नष्ट हो जाता है जब कोई संकट न हो। बिना संकट के भी ऐसे समाज के नष्ट होने की बात उन्होंने सम्भवतरू इसलिये कही होगी ताकि लोग इस बात को तार्किक वैज्ञानिक आधारों वाला कोई निष्कर्ष समझें और उन पर यह तोहमत न लगे कि वे लोगों को डरा रहे हैं या हिन्दू-मुस्लिम कर रहे हैं। उन्होंने कई भाषाओं और समाज के नष्ट होने की बात करते हुए लोगों को चेताया कि प्रजनन दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिये। इस वृद्धि दर को बनाये रखने के लिये लोगों को दो से ज्यादा (यानी तीन) बच्चे पैदा करने चाहिये। उन्होंने याद दिलाया कि देश में 1998 और 2002 में जो जनसंख्या सम्बन्धी नीतियां तय की गयी थीं उनमें भी 2.1 की दर को बनाये रखने की बात कही गयी थी। हालांकि उन्होंने अमूमन कम याददाश्त वाली जनता के सामने स्पष्ट नहीं किया कि ये दोनों नीतियां भारतीय जनता पार्टी प्रणीत नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस शासित कार्यकाल में लाई गयी थीं। चूंकि उनमें अनेक ऐसे राजनीतिक दलों का समावेश था जो इस मामले में दूसरी राय रखते थे, यह नीति कभी भी प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं हो पाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी वाली यह सरकार 2004 में जाती रही तथा उसके बाद आई यूनाइटेड डेमोक्रेटिक प्रंट की सरकार (पीएम डॉ. मनमोहन सिंह- दो कार्यकाल) ने इस अनर्गल विषय को तूल देने या बढ़ती आबादी को लेकर रोना-धोना करने की बजाय अधिकतम आबादी को काम देने की नीति पर कार्य किया। 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भी इस पर कोई काम करने की बजाय सियासी मुद्दा बनाकर समाज के भीतर उसे जिन्दा रखा। अपने पहले कार्यकाल (2014-19) के दौरान मोदी आबादी को लेकर एक सकारात्मक रैव्या अखिलयार करते नजर आये। उन्होंने अधिक जनसंख्या को, खासकर युवाओं की बहुलता के कारण भारत के लिये एक सौगत बताया। यह एक तरह से चीन की तरह की रणनीति अपनाने जैसा था जिससे बड़ी आबादी को अपनी ताकत बना दिया है। चूंकि पहले-पहल के मोदी भारत को चीन और अमेरिका के मुकाबले में लाने के दावे करते रहे, इसलिये कुछ समय तक तो उनकी पार्टी ने भी देश की आबादी बढ़ाने का दुखड़ा सुनाना बन्द कर दिया जो इसका ठीकरा अक्सर मुस्लिम समुदाय पर फैलते थे।

बचाव को मोदी सरकार की ओर से कॉरपोरेट हितों को बचाने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में ही देखा जा सकता है। अमेरिकी आरोप, जो संभावित थोखाधड़ी गतिविधियों, स्टॉक मूल्य हेफेर और अपततीय संस्थाओं से संबंधों की ओर इशारा करते हैं, न केवल कंपनी के संचालन के लिए बल्कि भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके व्यापक प्रभाव के रूप में एक गंभीर खतरा पेश करते हैं। अमेरिकी जांचकर्ताओं ने अडानी समूह के लेन-देन में गहराई से जांच की है, जिसमें अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार और घेरेलू निवेश विश्वास दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। स्थिति की गंभीरता के बावजूद, अडानी समूह और भारत सरकार की प्रतिक्रिया दूढ़ रही है। अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने कहा है कि उसके

विचार

महाराष्ट्र समाचार

दस्तूर ए हिंद के मोअलिफ, भारत के पहले वजीर-ए-कानून और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अबेडकर व बाबा-ए-कौम और मुजाहिद-ए-आजादी मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी (रह) को खिराजे अकीदत

मजलूमों को इंसाफ दिलाने, जात-पात, ऊँच नीच और आपसी भेदभाव को खत्म करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करने वाले दोनो अजीम रेहनुमाओं को पूरे मुल्क में याद किया जाएः एम. डबल्यु अंसारी (आई.पी.एस)



अंदर फैली तमाम तरह की बुराइयों को अगर खत्म करना है तो हमें तालीम यापता बनना होगा। इन रहनुमाओं ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों, मेहनत कशों, तालीम मआशी, सामाजी तौर पर नजर अंदाज और कमजोर दलित विरादिरियों की हमा-जहत फ्लाह-व-बहवूद कोशिशों में गुजार दी। आज मौजूदा हालात में देखा ज रहा है कि हर शोबे में, हर जगह, चाहे हो, प्रशासन है कही भी मनवादी और पुजवादी तत्व जिन कि आबाद सिंप से ज्यादा नहीं है लिकिन उन्होंने 45 से 95 परसेंट पर कब्जा कर रखा है। ऐ जनगणना होना चाहिए औ सभी कि हिस्पेदारी आबादी के हिसाब से है आज हम संविधान को बचाना है, साथ ही साथ मन्वाद और पुजवाद को खत्म है, भागना है। ईवीएम से चुनाव न है इस कि मेहनत करना है उन्होंने नारा भी दिया था कि दलित दलित एक समान चाहे हिन्दू हो या मुसलमान दोनों रहनुमाओं ने हमेशा लोगों से तालीम यापत बनने, मुत्तहिद होने, मेहनत करने और अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने, समाज के अंदर फैली बुराइयों से लड़ने और उसको खत्म करने, नाइंसापी व इसतेहसाल के खिलाफ आवाज बुलांद करने, भेदभाव, जात-पात की रवायत के खिलाफ लड़न, हक तल्पी करने वाले और हकतल्पी करने वाली पॉलिसियों के खिलाफ लड़न की बात कही। आज भारत को फिर से उसी जात-पात और भेदभाव की आग में झोंकने की कोशिश की ज रही है। समाज के लोगों को आपस में बांटा और लड़ाया जा रहा है। लोगों में नफरत फैलाई जा रही है। संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों के हुकूक क पामाल किया जा रहा है। ज़ुल्म-व-ज्यादती के खिलाफ आवाज बलांद करने वालों को खामोश करने के लिए

अडनी को जांच से बचाने का मोदी सरकार का निराशोन्मत प्रयास

के रवींद्रन

खिलाफ आरोप निराधार हैं, उन्हें गलतफहमी या सबसे खराब स्थिति में, अनुपालन में तकनीकी त्रुटियों के अलावा कुछ नहीं बताया जा सकता। भारत सरकार की ओर से अडानी समूह के बचाव को मजबूत राजनीतिक समर्थन मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने दावा किया है कि यह निजी संरथाओं से जुड़ा एक विशुद्ध रूप से कानूनी मामला है, और इसलिए, सरकार से चल रही कानूनी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, इस बयानबाजी ने अंतर्निहित प्रेरणाओं के बारे में संदेह को कम करने में बहुत कम मदद की है। मामले को वित्तीय कदाचार के गंभीर मामले के बजाय कानूनी तकनीकी मुद्दों के रूप में पेश करके, अडानी समूह और भारत सरकार दोनों ही रणनीतिक रूप से आरोपों की मूल प्रकृति से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रूप से एक समान रही है, भारत में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और यहां तक कि मीडिया आउटलेट्स ने अडानी समूह के पक्ष में दलीलें दीं तथा इसे वित्तीय घोटाले में उलझी कंपनी के बजाय विदेशी हस्तक्षेप का शिकार बताया। इस बचाव के व्यापक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह इस बात पर सवाल उठाता है कि भारत में कॉर्पोरेट प्रभाव किस हद तक सरकारी कार्रवाई से जुड़ा है। ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रसद में अपने विशाल व्यावसायिक हितों के साथ अडानी समूह भारत की सबसे प्रभावशाली कॉर्पोरेट संरथाओं में से एक है। इसका उदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक विकास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसके पछले दशक में अडानी समूह की धमकत की तरह वृद्धि को अक्सर देश की तेजी से बढ़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की इसकी आकंक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार, समूह का बचाव केवल एक कॉर्पोरेट मुद्दा नहीं है - इसे राष्ट्रीय हित का मामला बना दिया गया है। अगर भ्रष्टाचार के इन आरोपों को दबा दिया जाता है या महज तकनीकी बातों के तौर पर खारिज कर दिया जाता है, तो इससे पारदर्शिता और नैतिक व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में विश्वास कम होने का जोखिम है। अडानी समूह के राजनीतिक हस्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध अच्छी तरह से उत्तम हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन संबंधों ने समूह को नियामक जांच की पूरी सीमा से बचाने में मदद की है। इसलिए, समूह का बचाव करने में सरकार की भूमिका ने राजनीतिक आंभिजात वर्ग की संभावित मिलीभगत के बारे में चिंता जाताई है, जो जवाबदेही पर कॉर्पोरेट सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। अडानी समूह और भारत सरकार दोनों द्वारा निर्मित कथा एक निर्दोष पक्ष के रूप में सावधानीपूर्वक तैयार किये गये विच्रान पर टिकी हुई है, इस आरोप के साथ कि इसे विदेशी शक्तियों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। यह बयानबाजी एक व्यापक राष्ट्रवादी कथा की प्रतिध्वनि है जो घरेलू निगमों, विशेष रूप से सरकार के साथ निकटता रखने वालों को अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के शिकार के रूप में पेश करती है। आरोपों को भारत की संप्रभुता और इसकी आर्थिक उपलब्धियों पर हमले के रूप में पेश करती है। आरोपों को भारत की संप्रभुता और इसकी आर्थिक उपलब्धियों पर हमले के रूप में पेश करती है। और खद को विदेशी आलोचकों के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव के रक्षक के रूप में पेश किया है। हालांकि, यह राष्ट्रवादी रूपरेखा अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान हटाती है कि क्या अडानी समूह ने विकास और मुनाफे की तलाश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कानूनों और नैतिक मानदंडों का उल्लंघन किया है? यदि अमेरिकी अधिकारी अपनी जांच को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। अडानी समूह का निरंतर बचाव, खासकर अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो राजनीतिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। भारत सरकार खुद को एक मुश्किल स्थिति में पास की है, जिसे गहरे राजनीतिक संबंधों वाली एक शक्तिशाली कॉर्पोरेट इकाई का समर्थन करने या वित्तीय जवाबदेही के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ खुद को संरेखित करने के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कई मायनों में, अडानी का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे शक्तिशाली निगमों और राजनीतिक अभिजात वर्ग के हित एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वे लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रियाओं को विकृत कर रहे हैं, जिनकी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। जब सरकार गंभीर अपराधों के लिए जांच के दायरे में आई किसी कंपनी के पीछे खड़ी होती है, तो यह इस बात को लेकर परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है कि किस हद तक कॉर्पोरेट हित राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर रहे हैं। अडानी समूह कोई अलग उदाहरण नहीं है - अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित भारत में अन्य कॉर्पोरेट दिग्गज भी अलग-अलग जांच के साथ प्रभाव के ऐसे ही गलियारों में काम कर चके हैं।

दिल्ली सलाना फर बार-बार क्यों करते हैं किसान चढ़ाई?

अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा ? क्या उनकी मांगें भविष्य में कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं ? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर दौर में यही सब कुछ देखने को मिलता है। कमोबेस, सरकारों का रखवा सदैव एक जैसा ही रहता है। इसलिए एकाएक किसी सरकार को दोषी ठहराना किसी टिप्पणीकार के लिए बेईमानी सा होता है। किसान आंदोलनों से जो समस्याएं उपजती हैं, उसका खामियाजा सिफ्ट और सिर्फ आमजन ही भुगतते हैं। समस्याएं किस कदर पनपती हैं इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मरीज, छात्र, राहगीर, दैनिक कर्मी तो बेहाल होते ही हैं, रोजर्मर्ग के क्रियाकलाप भी रुक जाते हैं। दो दिसंबर को भी यही हुआ, जब किसान उत्तर प्रदेश के एक छोर से चले, तो सड़कों पर दौड़ने वाले तेज वाहनों के पहिए थम गए। क्या मरीज, क्या नौकरीपेशा, सभी के पैर अपने जगह रुक गए। दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार पिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बाँटिये पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार पिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। इस दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। अन्नदाता लंबा आंदोलन करने के मूड़ में दिखाई पड़ते हैं। इतना तय है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ, तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते एक महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगें मानी जाएं, उनसे बात करे कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकाल सकें। लेकिन उनकी बातों को हुक्मती स्तर पर एक बार भी अनुसुना और अनदेखा किया गया। दिल्ली पहुंचने के लिए गौंत्रमबुद्ध नगर से करीब 50,000



से अधिक किसान सोमवार सुबह यानी दो तारीख को नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्रित हुए, पिछले उद्घाटने दिल्ली कूच का स्थान किया, हालांकि तत्काल रूप से तो पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है। लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, वह किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है संसद का शीत सत्र चालू है। पूरी हुक्मती मशीनरी इस समय एक साथ है, उनकी बातें आसानी से पहुंच सकती हैं। पर, ऐसा होता दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार इतनी आसानी से सबकुछ मान लेगी, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए किसान भी काफी उग्र हैं। अपने साथ लंबे आंदोलन को करने के लिए तामझाम लेकर पहुंच हैं। राशन, टैक्टर, मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर, तंबू आदि हैं उनके पास।

किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अचानक से ही बनाया। पहले की प्री-प्लान नहीं थी। क्योंकि किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर पिछले कुछ दिनों से धरनागत थे। उनको प्रमुख मांग हैं, उन्हें जमीन के बदले 10 पर्सेंट निर्मित स्पॉट और 64 पर्सेंट बढ़ा हुआ जमीन का शेष मुआवजा दिया जाए। साथ ही जितने किसान जमीन छिन जाने से भूमिहीन हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई न कोई रोजगार जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। प्रस्तुतों की कीमतें डबर हों, खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों के रेट कम किए जाएं। जैसी पुरानी मांग भी उनकी बरकरार हैं। इस वक्त मैंडियों में धन की खरीद में जो घटतौली हो रही

नहीं पहुंच पाए। ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे, जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। किसान मूवमेंट शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही राजनीति भी आरंभ हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने कहा दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण गढ़ियां और अमित शाह की पूरी पुलिस तैनात की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे की उनको किसी आंतकवादी को रोकना या पकड़ना हो? किसान भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा और फसल के सही दाम की मांग लेकर दिल्ली आकर सोती सरकार को जगाना चाहते हैं इसमें बुरा क्या है? वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आया जिसमें कहा गया कि राष्ट्र की राजधानी किसी की बपाती तो है नहीं? फिर किसान क्यों नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री पर भी उहोंने हमला किया।

दिल्ली मेट्रो की केवल चोर काटकर ले गए, लूप लाइन पर सेवाएं हुई बाधित

नईदिल्ली। दिल्ली मेट्रो की लूप लाइन पर गुरुवार को केवल चोरी की वजह से सेवाएं प्रभावित हुई हैं। भोटी नार और कीर्ति नगर के बीच इस घटना के कारण मेट्रो ट्रेनों की गति जीपी की दी गई, रेल कॉर्पोरेशन ने इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रभावित खड़ पर मरमत कार्य आज रात परेवान थंटों के बाद पूरा किया जाएगा। डीएमआरसी की ओर से यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा के लिए अतिरिक्त समय का प्रावधान रखें। दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना विलंब की घटना में रखते बाबा। प्रभावित खड़ पर मरमत कार्य आज रात परेवान थंटों के बाद पूरा किया जाएगा।

डीएमआरसी की ओर से यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा के लिए अतिरिक्त समय का प्रावधान रखें। इस तरह की घटनाएं से न केवल मेट्रो रेल पर घटना होती है, बल्कि यात्रियों को भी काफी असुविधा होती है।

फले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं।

यह पहली बार नहीं है जबकि केवल चोरी से सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अगलते में भी रेल लाइन पर झिलमिल और मानसरोरह पार्क रेस्टोरेंटों के बीच सिंगल रेल चोरी हुई है जिससे दिल्ली गार्डन से शहरदार मार्ग पर ट्रेनों को रोटार घटाकर 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी।

जब अभिनेता सलमान खान के शूटिंग सेट पर घुसा अनजान युवक

- गैरगर्द का नाम लेते ही मुंबई पुलिस ने निया दिसात में

मुंबई। मुंबई के दादर इलाके में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के शूटिंग सेट पर एक शख्स अवैध रूप से घुसा गया। शक होने पर जब उसके पूछातां की गई तो उसने कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को कहूँ दूया? इसके बाद सादेह को पूछातां के लिए शिवायी पार्क पुलिस रसेन्ट ले जाया गया। मिली जानकारी के तुरंतिक ये घटना मुंबई के प्रिमियल 5 में हुई। सादियं ने कथित तौर पर गैरगर्द और लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया। प्रतिस उसकी जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब यह अज्ञात व्यक्ति अंतर आया तो सलमान खान शूटिंग के लिए रुकूम थे। जब उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया तो रुकूम से कुछ लोगों ने उसे देख लिया। फिर इसकी सुनना और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कर्ड रुपये की फिराई भी आयी। इसके बाद देखिए कि पिछले कुछ समय से सलमान खान के लैंगर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई बार धमनी की भी लिपि चुकी है। हाल ही में उनसे 5 करोड़ रुपये की फिराई भी आयी। कुछ महीने पहले सलमान के बांद्रा रिश्त घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी। इसमें लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। कुछ दिनों पहले सलमान खान के सबसे अच्छे दोस्त और राज्य के पर्व में बाली बाली शिरीखी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से सलमान की सुरक्षा का ख्याल और भी सजगता से रखा जाने लगा है।

मणिपुर हिंसा : थौबल में भारी मात्रा में मिले हथियार, दुष्कर्मी उप सरपंच भी गिरफतार

इफाल। मणिपुर के थौबल जिले में तलाशी अधियान के दौरान 16 आन्याश्रम, ज्ञान 36 एचर ग्रेड, दो डेटोनेटर, गोला-बालू और एक वींटी-टीकों-से टके साथ एक चांगर बमामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि यह बरामदी बुधवार को फूटी गयी थी। अप्रैल के बाद देखिए कि पिछले कुछ समय से सलमान खान के लैंगर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यूप्राय प्रसार के मृत्युजंजिली के लिए ब्रॉडजॉली दी गई। समात परिषद मुंबई संस्था के अध्यक्ष व बाली भंडारी के विभाग जिलों में कुल मिलाकर 10 जांच विकाया स्थापित की गई हैं और कानूनों के फिराई भी उल्लंघन के संबंध में किसी को दिवानांकन से बचाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्वरासेवक दिविस के अवसर पर डॉ. जियाकुमार दिल्ली के अधिकारी ने अपने मध्यसंस्कार के लिए ब्रॉडजॉली दी गई और इंडियन गोली भंडारी के लिए ब्रॉडजॉली दी गई। अप्रैल के बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई बार धमनी की भी लिपि चुकी है। हाल ही में उनसे 5 करोड़ रुपये की फिराई भी आयी। कुछ महीने पहले सलमान के बांद्रा रिश्त घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी। इसमें लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। कुछ दिनों पहले सलमान खान के सबसे अच्छे दोस्त और राज्य के पर्व में बाली बाली शिरीखी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से सलमान की सुरक्षा का ख्याल और भी सजगता से रखा जाने लगा है।

गांधीधाम में फर्जी ईडी टीम का पर्दाफाश, महिला समेत 12 आरोपी गिरफतार

कच्छ। गुरुवार में अब तक फर्जी डॉक्टर, फर्जी हॉपिटल, फर्जी पुलिस, फर्जी जन फर्डे जाने की घटना समेत आ चुकी हैं। अब गुरुवार में फर्जी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम कानून के हत्ये छढ़ गई है। योकाने गाली बाल रुक है कि फर्जी ईडी की टीम में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने महिला समेत 12 आरोपीयों को गिरफतार किया। इसके बाद रुपये का माल-सामान भी जब लिया गया। दरअसल फर्जी ईडी अधिकारी बनकर 2 दिसंबर को काढ़ के गांधीधाम इलाके में राधिका जैलर्स और उनके आवासीय पर में एक गिरेव ने हाथ साफ कर दिया था। गिरेव ने खुद को ईडी की अधिकारी बनाते हुए साना, चांदी और नकदी सहित रु. 25,225 मूल्य की कीमीयी योंगे चुरा ली। घटना के बाद राधिका जैलर्स के गालिक ने गांधीधाम ए डिविजन पुलिस संस्थान में शिकायत दर्ज की थी जिसके आधार पर पुलिस की अलान-अलान गाली की थुक्का, गाली की अलान-अलान गाली तो जारी रहा। अब महाद्वारा समेत अन्य जगहों पर जारी शुरू कर दी गयी जो अलान-अलान गाली की घटना से बदल चुकी है।

इसके बाद देशभर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे।

पुष्पा 2 को बांद्रा के गेयटी गैलेक्सी में बिच मै रोकना पड़ा

मुंबई / अकबर खान

मुंबई अर्जुन की मोस्ट अटेंटेड फिल्म 'पुष्पा 2 द रूल' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। वही बांद्रा के गेयटी गैलेक्सी में इस फिल्म को बिच मै रोकना पड़ा।



दिसंबर को रात 9:30 बजे हैं दैरावाद के संचार थिएटर में स्पेशल शो शुरू हुआ तो खुद अल्लू अर्जुन भी बांद्रा मैजूद थे। तो चलिए जानें कि अधिक बिचमारों से लौट रहे दर्शकों को यह फिल्म कैसे लग रही है?

पुष्पा 2 पहले ही दिन बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। डेटे एलाइंस तरंग आदर्श के मोस्ट अटेंटेड फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' की नजर दो बड़े रिकॉर्ड पर-एक 'जवान' और सेकेंड 'एनिमेशन'। 65.5 करोड़ के साथ 'जवान' के नाम अवैध रिकॉर्ड के बाद निर्वाचन प्राप्त करता है। दूसरे बांद्रा याद देखने के लिए बांद्रा रिकॉर्ड पर उत्तम विवरण प्राप्त करता है। वह समाजिक इंसाफ के लिए बांद्रा याद का अलावा अन्य विवरण भी आवश्यक है।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 पहले ही दिन बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। डेटे एलाइंस तरंग आदर्श के मोस्ट अटेंटेड फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' की नजर दो बड़े रिकॉर्ड पर-एक 'जवान' और सेकेंड 'एनिमेशन'। 65.5 करोड़ के साथ 'जवान' के नाम अवैध रिकॉर्ड के बाद निर्वाचन प्राप्त करता है। दूसरे बांद्रा याद देखने के लिए बांद्रा रिकॉर्ड पर उत्तम विवरण प्राप्त करता है। वह समाजिक इंसाफ के लिए बांद्रा याद का अलावा अन्य विवरण भी आवश्यक है।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लैंगर रहा।

पुष्पा 2 के पुस्तक रात जालवा का लै

